

संपादकीय भाषाओं को बचाने की भारतीय पहल

छोटी सी योजना की शुरुआत

प्रधान न्यायाधीश डीवार्ड चंद्रचूड ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट अब व्हाट्सएप संदेशों द्वारा जानकारी साझा करेगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी के पिछलतरवें वर्ष में यह छोटी सी योजना की शुरुआत की है। व्हाट्सएप के रोजाना की जिंदगी में शामिल होने और इसके शक्तिशाली संचार सुविधा होने की बात भी उन्होंने की। इस पहल के अंतर्गत एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तथा शीर्ष अदालत के समक्ष निजी तौर पेश होने वाले वादियों को मुकदमा ऑनलाइन दाखिल करने, वाद सूची, आदेशों तथा निर्णयों के संबंध में जानकारी प्राप्त होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे क्रांतिकारी कदम बताते हुए इसकी सराहना की। प्रधान न्यायाधीश ने व्हाट्सएप नम्बर साझा करते हुए स्पष्ट किया कि इस पर कॉल या संदेश प्राप्त नहीं होंगे। निसंदेह यह सबसे बड़ी अदालत को पेपरलेस बनाने की तरफ उठा बड़ा कदम है। तकनीक संबंधी सुविधाओं को जितनी जल्दी हो सके रोजमरा की जिंदगी में शामिल कर लेना उचित होता है। प्रधान न्यायाधीश निरंतर अदालती काम को लेकर ऐसी व्यवस्थाएं दे रहे हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट जजों में सबसे ज्यादा फैसले लिखने का रुतबा प्राप्त है। छह वर्ष के भीतर 513 फैसले लिख चुके हैं। न्याय व्यवस्था को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए समय-समय पर उन्होंने बड़े कदम उठाए हैं। विभिन्न फैसलों को उन्होंने क्षेत्रीय भाषा में अनुदित करवाने की व्यवस्था करके तथा हिन्दी, तमिल, उडिया और गुजराती में फैसलों का अनुवाद करने के लिए समिति का गठन भी किया। देश में 48 करोड़ से अधिक व्हाट्सएप प्रयोगकर्ता हैं, जो 2025 तक 80 करोड़ तक पहुंचने का अंदाजा है। हालांकि व्हाट्सएप मेटा टेक्नोलॉजी कंपनी की सुविधा है, जिसके सीईओ मार्क जकर्बर्ग हैं। किसी भारतीय संचार संस्थान को इस जरूरत को समझते हुए आगे कदम बढ़ाने की सख्त जरूरत है। सरकार, देश के अन्य बड़े संस्थान और गोपनीय दस्तावेज के लिए देसी तकनीक का प्रयोग किया जाना उचित है। तकनीक के मामले में हम दूसरों पर निर्भर होते जा रहे हैं। यह बड़ी चुनौती है। बाबूजूद इसके तकनीक का इस्तेमाल सुविधाओं के लिए करना वक्त की मांग है, इसके बिना काम नहीं चल सकता।

विशेष लेख

समूचा विश्व भयाक्रांत

शांत क तमाम उपायों क बाच दुनिया भर में सैन्य खर्च, शस्त्रीकरण एवं धारक हथियारों की होड़ खतरे की घंटी हैं। शस्त्रीकरण के भयावह दुष्परिणामों से समूचा विश्व भयाक्रान्त है। हर पल आणविक हथियारों के प्रयोग को लेकर दुनिया डर के साथे में जी रही है। इसीलिए आज अयुद्ध, निश्चीकरण एवं शांति की आवाज चारों ओर से उठ रही हैं। शक्ति संतुलन के लिए शस्त्र-निर्माण एवं शस्त्र संग्रह की बात से किसी भी परिस्थिति में सहमत नहीं हुआ जा सकता बर्तोंकि इससे अपव्यय तो होता ही है, साथ ही गलत हथियारों के हाथों में पड़कर दुरुपयोग की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। ताजा घटनाक्रम को देखें तो एक ओर रूस और यूक्रेन आमने-सामने हैं, दूसरी तरफ इन्हीं और ईरान के बीच तल्खी भी चरम पर है। चीन और ताइवान के बीच भी रह-रह कर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे माहौल में सवाल स्वाभाविक है कि क्या सचमुच दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ते हुए धारक हथियारों की प्रयोगभूमि बन रही है? सवाल और भी हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हथियारों पर ताजा रिपोर्ट ऐसे ही सवाल खड़े कर रही है। दुनिया सीधे-सीधे दो खेमों में बंट गई है। स्टॉकहोम की रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले ही नहीं, डराने वाले भी हैं। शांति के तमाम उपायों के बीच दुनिया भर में सैन्य खर्च का बढ़ना एवं नये-नये हथियारों का बाजार गरम होना, चिंताजनक है। रिपोर्ट में खास बात यह है कि दुनिया में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत चौथे नंबर पर बरकरार है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। भारत ने बीते पांच साल में दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदे। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोप का हथियार आयात 2014-18 की तुलना में 2019-23 में लगभग

प्रमोद भार्गव

प्रतिस्पर्धा के दौर में मातृभाषा को लेकर युवाओं में हीनभावना भी पनप रही है। भाषाओं को बचाने के लिए समय की मांग है कि क्षेत्र विशेष में स्थानीय भाषा के जानकारों को ही निगमों, निकायों, पंचायतों, बैंकों और अन्य सरकारी दफ्तरों में रोजगार दिए जाएं। इससे अंग्रेजी के फैलते वर्चस्व को चुनौती मिलेगी और ये लोग अपनी भाषाओं व बोलियों का संरक्षण तो करेंगे ही, उन्हें रोजगार का आधार बनाकर गरिमा भी प्रदान करेंगे। ऐसी सकारात्मक नीतियों से ही युवा पीढ़ी मातृभाषा के प्रति अनायास पनपने वाली हीनभावना से भी मुक्त होगी। इस नजरिए से 52 क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई एक अनूठी और आवश्यक पहल ह कोई भी भाषा जब मातृभाषा नहीं रह जाती तो उसके प्रयोग की अनिवार्यता में कमी और उससे मिलने वाले रोजगार मूलक कार्यों में भी कमी आने लगती है। पिछले 75 सालों में हमारी भाषाओं और बोलियों के साथ यही होता रहा है, परंतु अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी) को लागू करने की दिशा में उल्लेखनीय पहल करते हुए केंद्र सरकार नए सत्र से पांच नए उपाय करने जा रही है। इनमें बच्चों को मातृ, घरेलू और क्षेत्रीय भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस लक्ष्यपूर्ति के लिए 52 प्रवेशिकाएं अर्थात पाठ्य-पुस्तकें तैयार की गई हैं। इनसे छात्र-छात्राओं से लेकर वयस्क तक वर्णमाला और दो अंकों तक गणित सीख सकेंगे। पहले चरण में 17 राज्यों की राजभाषा व स्थानीय भाषा में 52 पुस्तकें मैसूर के भारतीय भाषा संस्थान और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने तैयार की हैं। देश में ऐसी 121 भाषाएं हैं जिन्हें क्षेत्रीय लोग स्थानीय स्तर पर लिखने व बोलने में प्रयोग करते हैं। जल्दी ही देश के बाकी राज्यों की अंचलिक भाषाओं में प्रवेशिका उपलब्ध करा दी जाएंगी। इन पाठ्य पुस्तकों का उपलब्ध होना न केवल विद्यार्थियों के लिए, बल्कि विलोपित हो रही मातृभाषाओं का अस्तित्व बचाए रखने की



परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल निर्बाध और भविष्यवादी शिक्षण परिदृश्य तैयार कर भारतीय भाषाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी। इससे नई शिक्षा नीति का दृष्टिकोण साकार होगा और शालेय शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे। सरकार ने राष्ट्रीय विद्या समीक्षा केंद्र का राज्य इकाइयों व 200 डीटीएच चैनलों के साथ एकीकरण का निर्णय भी लिया है। इस हेतु सरकार ने 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 22 क्षेत्रीय व प्रादेशिक भाषाओं में चैनल तैयार कर लिए हैं। ये बिना इंटरनेट चलेंगे। भविष्य में ये चैनल ओटीटी और यू-ट्यूब पर भी उपलब्ध होंगे। भारत में ऐसे हालात समाने भी आने लगे हैं कि किसी एक इनसान की मौत के साथ उसकी भाषा का भी अंतिम संस्कार हो जाए। 26 जनवरी 2010 को अंडमान द्वीप समूह की 85 वर्षीय बोआ के निधन के साथ ग्रेट-अंडमानी भाषा ‘बो’ भी हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। इस भाषा को जानने, बोलने और लिखने वाली वे अंतिम इनसान थीं। इसके पूर्व नवंबर 2009 में एक और महिला बोरो की मौत के साथ खोरा भाषा का अस्तित्व समाप्त हो गया था। नेशनल ज्योग्राफिक सोसायटी एंड लिविंग टंग्स इंस्टीट्यूट फॉर एंडोर्जड लैंग्वेजेज के अनुसार हरेक पखाड़े एक भाषा की मौत

चुनावी समय में सोशल मीडिया बना चाणक्य

डा. नाई शर्मा

इसका ताजा उदाहरण रणवीर सिंह एवं अमिर खान के साथ हुई घटना से पता लगता है। इन द्विविधाओं का समाधान जनता की तार्किक सावधानी ही है, क्योंकि कोई सूचना जब अत्यधिक बेग, हिंसा व उत्तेजना पैदा करे तो शक्ति होना लाजिमी है। कुछ देर ठहरए और मन को शांत कर सोचिए। क्योंकि जनता के जुड़ाव के लिए असंख्य सूचना का ऐसा समुद्र खड़ा कर दिया गया है जिसमें तैरना स्वयं सीखना पड़ेगा। क्योंकि जनता इस समय एंग ली द्वारा निर्देशित फिल्म लाइफ ऑफ पाई के मुख्य किरदार पाई की भाँति खड़ी है जहां उसे सूचना के बवंदर से स्वयं बचना होगा आज के समय में वही उम्मीदवार जनता का पसंदीदा बन जाता है जो सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंच बनाता है क्योंकि जो दिखाता है वही बिकता है, इसी बाजार की रणनीति को आज सभी राजनीतिक पार्टियां अपना रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि विज्ञापन को जांचने व परखने के लिए कई जांच एजेंसियां व प्रतियोगी कंपनियां अन्य कंपनियों के खिलाफ भ्रामकता के आधार पर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। इसका हालिया उदाहरण देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन देने के लिए फटकार लागाई और इसके साथ-साथ इस कंपनी के खिलाफ याचिकाकर्ता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी आडे हाथों लिया। कोर्ट ने एलोपैथी डॉक्टरों का जनता के शरीर पर पड़ने वाले नकारात्मक असर का चिंतन तो उजागर होता है, लेकिन हर दिन सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले कटेंट का लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव की जिम्मेवारी कौन लेगा? इन दिनों चुनावी समय में तो हर राजनीतिक पार्टी स्वयं भी और इंफ्लुएंसर के माध्यम से देश के हर तबके तक पहुंचने के लिए प्रभावी सामग्री का प्रयोग अनिवार्य रूप से कर रही है। यह सामग्री कितनी सही है और कितनी गलत, इसके लिए न तो कोई सरकारी मशीनरी है और न ही कोई एजेंसी। हालांकि चुनाव आयोग सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव प्रसार संबंधित सामग्री को जांचने के लिए हर जिले व राज्य स्तर पर बनाए गए कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सामग्री साधारण न होकर अब अर्टिफिशियल इंटेलीजेंस से भी बनाई जा रही है जिससे निपटना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसके अलावा चुनाव आयोग तो आचार संहिता लागू होने के बाद से ही एकट बुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां पिछले एक साल से अपने प्रचार-प्रसार में जुट गई हैं। यह बात इससे सिद्ध होती है कि यह वर्ष शुरू होते ही चुनावों को देखते हुए देश की राजनीतिक पार्टियों ने पहले 2 से 3 महीनों में मेटा एवं गूगल विज्ञापन में 102.7 करोड़ खर्च कर दिए। वहीं भाजपा पिछले एक

साल से सरल नाम की ऐप के जरिए जनता से संपर्क बनाने में लगी हुई है, जिसे लगभग 2.9 मिलियन लोग डूगल प्ले स्टोर के जरिए डाउनलोड कर चुके हैं। वहीं वेपक्षी गठबंधन भी सामाजिक न्याय, किसान, युवा व ब्रिजेजारी जैसे मुद्दों को सोशल मीडिया के विभिन्न लेटरफर्म से उठाकर बड़ा अभियान चला रहा है। लेकिन फिर सवाल सिर्फ इतना है कि इन पार्टियों द्वारा दी जा रही सूचना कितनी विश्वसनीय है? सोशल मीडिया के प्रति दीवानगी इतनी है कि डिजिटल सलाहकार फर्म कैपियोस के मुताबिक दुनिया भर में 520 करोड़ लोग सोशल मीडिया की अलग-अलग साइट्स का प्रयोग करते हैं जिनकी संख्या सालाना 3 से 4 प्रतिशत बढ़ रही है। वहीं हमारे देश में आईआईएस रोहतक के एक अध्ययन के मुताबिक लगभग 62 प्रतिशत युवा जानकारी के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न लेटरफर्म उपयोग करते हैं जिनमें से एक पुरुष औसतन स्क्रीन रुपर 6 घंटे 45 मिनट और महिला 7 घंटे 5 मिनट व्यतीत करती है। यानी कि सोशल मीडिया ही सूचना का मुख्य स्रोत बन चुका है। इस संदर्भ में सूचना का प्रवाह और उसकी संरचना मानवीय व्यवहार पर प्रभाव डाल रही है। चुनावी समय में पार्टियां अन्य समय से दुगनी अप्टार के साथ अपने ऑनलाइन सामग्री के माध्यम से जनता को जोड़ने की कोशिश करती हैं। जिस पार्टी की गति जितनी नवनीतम और तेज होती है वो उसी गति से नए बोटर व समर्थन हासिल करने में कामयाब हो जाती है। खास बात यह है कि इन सोशल मीडिया साइट्स के मालिक इस समय में नियंत्रण करने के बजाय मूकदर्शक बन जाते हैं क्योंकि यह समय पैसा बनाने का है। इस बिंदु पर न तो कोई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कानून उहें नियंत्रण कर सकते में सक्षम है। इस मौके का पर्यादा उठाकर पर्टियां अनियंत्रित तरीके से नियोजित वर्ग में किसी भी तरीके से अपनी पहुंच बढ़ाती हैं और उनके आईटी सैल जनता की भावनाओं को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया की एलोरिंटम के कारण आपका हल्का सा भी झुकाव फेंक न्यूज के जंजाल में फैसा देता है और जनता इको चैम्बर से बाहर ही नहीं निकल पाती। वो अभेद्य चक्रव्यूह बन जाता है जिसमें जनता बिना कुछ सौचे-समझे बस फैसती ही चली जाती है।

और रही-सही करस डीपफेक वीडियो ने पूरी कर दी है जहां प्रसिद्ध व्यक्तियों को ढाल बनाकर कुछ गलत तत्व अपने उद्देश्यों को पूरा करने में लगे हुए हैं। इसका ताजा उदाहरण रणवीर सिंह एवं आमिर खान के साथ हुई घटना से पता लगता है। इन दुविधाओं का समाधान जनता की तार्किक सावधानी ही है, क्योंकि कोई सूचना जब अत्यधिक वेग, हिंसा व उत्तेजना पैदा करे तो शक्ति होना लाजिमी है। कुछ देर ठहरिए और मन को शांत कर सोचिए। क्योंकि जनता के जुड़ाव के लिए असंख्य सूचना का ऐसा समुद्र खड़ा कर दिया गया है जिसमें तैरना स्वयं सीखना पड़ेगा। क्योंकि जनता इस समय एंग ली द्वारा निर्देशित फिल्म लाइफ ऑफ पाई के मुख्य किरदार पाई की भाँति खड़ी है जहां उसे सूचना के बवंडर से स्वयं बचना होगा और अपने मानसिक विकास व उत्तरजीविता के लिए स्वयं सोचना होगा।

इलेक्ट्रॉनिक मशीन जायेगी तो फिर से होगा बूथ कैप्चरिंग

स्वाति

भारत गणराज्य 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 18वें आमचुनाव की तैयारी कर रहा है जो विश्व का सबसे बड़ा चुनाव होगा, जब 96.88 करोड़ मतदाता अपने जनप्रतिनिधि का चयन करेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किये हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाकर एक समूह ने पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर ही सवालिया निशान लगाने की कोशिश की है। इस सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट अरुण कुमार की याचिका की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और सरकार से बीवीपैट की सभी पर्चियों का मिलान ईवीएम में पड़े सभी बोटों से कराने की वास्तुस्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा है। अभी की व्यवस्था में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के रैंडम पांच ईवीएम का ही बीवीपैट से मिलान होता है। याचिका के अनुसार इस कारण मतदाता के मन में प्रणाली को लेकर सदैह उत्पन्न होता है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि मतदाता को बीवीपैट की पर्ची को खुद बैलेट बॉक्स में डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी और मतदाता यह देख लेगा कि उसका मत सही व्यक्ति को पड़ा है और यह गणना के लिए भी जाएगा। आगे यह बात भी उठाई गई है कि चुनाव आयोग 24 लाख बीवीपैट के लिए 5 हजार करोड़ खर्च कर चुकी है मगर सिर्फ 20,000 बीवीपैट का उपयोग समझ के परे है। न्यायालय ने सरकार और चुनाव आयोग को जवाब तलब तो किया है मगर क्या वार्कइ बीवीपैट की पर्ची से ईवीएम में पड़े बोट का रैंडम मिलान चुनाव प्रणाली के निष्पक्ष होने की गारंटी नहीं दे पाता या ईवीएम हैक और बीवीपैट पर्ची से मिलान जैसे मुद्रे जानबूझकर उठाये जा रहे हैं ताकि जनता के मन में सदैह पैदा हो अभी पिछले साल सितंबर में भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई थी जिसमें ईवीएम से चुनावी धार्थी और गड़बड़ी की बात कही गई थी। मगर याचिका पर



न्यायालय ने फटकार ही लगाई थी कि हर कुछ दिनों में ईवीएम की गड़बड़ी का शिगूफा छोड़ना और भ्रम उत्पन्न करना गलत है। हालांकि चुनाव आयोग ने तब भी न्यायालय को बताया था कि ईवीएम बिना किसी कंप्यूटर या इंटरनेट नेटवर्क के स्वतंत्र रूप से काम करने वाली बन टाइम प्रोग्रामेल चिप वाली मशीन है, जिससे हैंकिंग या डेढ़छाल असंभव है। आयोग ने बताया था कि अब तक सिर्फ 25 शिकायतें मिली हैं जो भी जांच के बाद झूठी पाई गई हैं। ईवीएम और वीवीपैट पर प्रश्न उठाने से पहले इसे समझना जरूरी है। वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रैल एक मशीन होती है जो वोटिंग के समय बताती है कि वोटर ने किसे वोट दिया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से कनेक्ट किया जाता है। ईवीएम में मतदाता जिस भी पार्टी का बटन दबाता है, उसी पार्टी के चिह्न की पर्ची वोटर को वीवीपैट मशीन में दिखती है। वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची सिर्फ वोटर को ही दिखती है। अब यह प्रणाली अभी रेंडम है तो भी क्या अब तक सभी 20,000 वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम के बोटों से मिल जाना स्वयं में इसके निष्पक्षता का सबत

नहीं है रैडम चुनाव तो फिर भी गडबड़ियों की आशंका को कम करता है। सिलसिलेवार जब यही प्रक्रिया अपनाई जाने लगेगी और पर्चियों से ही बोटिंग की गणनी होने लगेगी तो इस बात की क्या गारंटी है कि बब विपक्ष यह आरोप नहीं लगाएगा कि पर्चियों को ही बदल दिया गया या फिर ईवीएम को ही रीसेट कर बोट को ही बदल दिया गया संदेह लाइलाज होता है। असंतुष्ट को कल्पवृक्ष भी संतुष्ट नहीं कर सकता। फिर भी ईवीएम के मामले में एक और बात समझने की जरूरत है। हाल ही जर्मनी की कोर्ट ने जर्मनी में ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसकी असलियत और कारण क्या है इसे समझने की जरूरत है। सबसे पहले यह बात समझना होगा कि यहां भी न्यायालय में दो याचिकाएं थीं जिसमें एक ईवीएम के उपयोग को असंवैधानिक घोषित करने की थीं और दूसरी ईवीएम के हैक होने की संभावना की वजह से इसको बैन करने की थी। जर्मन न्यायालय ने हैक करने वाली याचिका को खारिज किया और बेमानी बताया। वहां की अदालत ने इसके उपयोग को पूर्ण रूप से वर्जित नहीं किया है। हां न्यायालय ने जर्मन संविधान के अनुसार

इसे कुछ आधार पर असंवेद्यानिक जरूर ठहराया है। न्यायालय ने कहा कम्प्यूटर में पड़े मत को जनता नहीं देख पाती जो जर्मनी संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन है। जापान ने इस प्रक्रिया को महंगा बता कर बंद किया जो बहुत बड़ा कारण भारत में भी वीवीपैट की अनुपलब्धता का है। जर्मनी और जापान दोनों देशों ने पारदर्शिता में अभाव को माना जिसका अर्थ वीवीपैट जैसे मशीनों से रैंडम क्रॉस वेरिफाई ना कर पाना है। नीदरलैंड के मामले में पारदर्शिता के अलावा मशीनों के भंडारण, परिवहन एवं सुरक्षा को लेकर नियमों का अभाव था। अमेरिका में ईवीएम का उपयोग लगभग न के बराबर है और वो मतपत्रों से मतदान को अपने रिच्युअल से जोड़ कर देखते हैं और परंपरा ऐसे ही रखना चाहते हैं। भारत में भी चुनाव आयोग ने इस बात को स्पष्ट किया है कि इन देशों में वीवीपैट जैसी किसी मशीन का उपयोग नहीं होता और बैन किए गए देशों में ईवीएम एक कम्प्यूटर और नेटवर्क से जुड़ा होता है जिसे हैक करना संभव है। हमें नहीं भूलना चाहिए भारत में मतपेटियों को लूटने का इतिहास रहा है। इसे ही रोकने के लिए ईवीएम को सुरक्षित विकल्प के तौर पर अपनाया गया था ताकि वोटों की लूट रोकी जा सके। आज भी बंगल के पंचायती चुनाव में मतपेटियों की लूट के किस्से सरेआम हैं। ऐसे में क्या गारंटी है कि अगर ईवीएम को हटा दिया जाएगा तो पुनः बूथ कैचरिंग नहीं शुरू हो जाएगी देश की जनसंख्या इतनी है कि मतपत्र द्वारा वोट देना और उसकी गिनती करना एक थकाऊ और खर्चाली प्रक्रिया होगी। जो लोग जर्मनी, जापान और अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं वो लोग पड़ोस के पाकिस्तान को क्यों नहीं देख रहे हैं जहां सरेआम आज भी बैलट बॉक्स लूटकर मनमाना नहीं जानिकाला गया है भारत की परिस्थितियां अमेरिका जैसी नहीं बल्कि पाकिस्तान जैसी ही हैं। यह ईवीएम ही है जिसने बदनाम बूथ कैचरिंग और वोटों की लूट पर रोक लगाई है। जो लोग बार बार इस पर सवाल उठा रहे हैं क्या वो फिर से बूथ कैचरिंग का गस्ता खोलना चाहते हैं

संक्षिप्त समाचार

वी एसओसी2, टाईप2 अटेस्टेशन
पाने वाला उद्योग जगत का पहला
प्लेयर बना; उपभोक्ताओं के भरोसे
एवं डेटा सुरक्षा के लिए अपनी
प्रतिबद्धता की पुष्टि की

मुंबई : जाने-माने दूरसंचार सेवा प्रदाता बोडाफ़ेन आइडिया (वी) ने आज बताया कि इसे एसओसी2 टाईप्ड 2 अटेस्टेशन मिला है। वर्तमान में यह भारत का एकमात्र दूरसंचार सेवा प्रदाता है, जिसने सफलतापूर्वक एसओसी2 टाईप्ड 2 अटेस्टेशन को पूरा कर लिया है। यह उपभोक्ताओं की संवेदनशील जानकारी एवं गोपनीयता को सुरक्षित रखते हुए तथा डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल-ऑफ-सर्विसेज़ (डीडीओएस) अटैक को कम करते हुए डेटा सुरक्षा के सर्वोच्च मानकों को बरकरार रखने की वी की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। एआईसीपीए (एसेसिएशन ऑफ़इंटरनेशनल सर्टिफाईड प्रोफेशनल अकाउन्टेन्ट्स) के साथ रजिस्टर्ड स्वतन्त्र सीपीए और विस्ता इन्प्रेसेक द्वारा संचालित सख्त मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद प्राप्त यह मान्यता एसओसी 2 'ट्रस्ट सर्विस' पर आधारित है, जिसके तहत मुख्य मानकों जैसे सुरक्षा, उपलब्धता, प्रोसेसिंग इंटेरियरी, गोपनीयता आदि पर उपभोक्ताओं के डेटा प्रबन्धन का मूल्यांकन किया जाता है। यह मान्यता इस बात की पुष्टि करती है कि कंपनी न सिर्फ जटिल सुरक्षा नीतियों के कार्यान्वयन में सक्षम है बल्कि विस्तारित अवधि के लिए अनुपालन को भी प्रमाणित करती है। एसओसी2 टाईप्ड 2 ऑडिट इस बात की पुष्टि करता है कि वी का भीतरी नियन्त्रण, नीतियां एवं प्रक्रियाएं सुरक्षा एवं संचालन दक्षता के सर्वोच्च मानकों पर आधारित हैं।

पर मिनोचा कालोनी के पास बन रही सड़क के डामरीकरण का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है, जो लगभग पूरा होने की स्थिति में बिलासपुर के शहरवासियों को जल्द ही मिलेगी। एक नई सड़क उत्सलापुर रोड में मिनोचा कालोनी के समीप महावीर नगर चौक से उत्सलापुर ओवरब्रिज तक बिलासपुर स्टार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 900 मीटर पहले सड़क के किनारे नाली बनाने का काम पूरा किया जा रहा है। इससे पहले सड़क के किनारे नाली बनाने का काम पूरा किया जा रहा है।

वह इस बात का संकेत है कि डीडीओएस सुरक्षा के सर्वोच्च स्तर के साथ सुरक्षा नियन्त्रण के लिए वी के पास सशक्त डिज़ाइन एवं संचालन दक्षता है। सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे को यह तेजी से पहचान लेता है, ऐसे में यह सभी कारोबारों के लिए भरोसेमंद सेवा प्रदाता है। वी को 2022 में एसओसी टाईप 1 अटेसेशन मिला था, जिसने यह स्पष्ट किया कि वी द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाने वाली वेवाएं पूरी तरह से सुरक्षित और नियमों के अनुरूप हैं। अब एसओसी 2 टाईप 2 अटेसेशन इस बात की गुणित करता है कि कंपनी लगातार सुरक्षा प्रक्रियाओं का अनुपालन कर रही है, जिसका मापन 6 से 12 महीनों की अवधि के लिए किया गया है।

**बीई/बीटेक प्रोग्राम्स में
एकेडमिक एक्सीलेंस दे रहा
थापर इंस्टीट्यूट ऑफ
इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी**

रायपुर। थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (डीम्ड यूनिवर्सिटी) में बीई/बीटेक एडमिशन 2024 के लिए एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। ये एडमिशन जेर्डी मेन 2024 की आल इंडिया रैंक और 12वीं की पीसीएम मेरिट को ध्यान में रखकर दिए जा रहे हैं। लेटरल एंट्री एडमिशन 10वीं के बाद तीन साल का डिप्लोमा या 12वीं के बाद दो साल का डिप्लोमा करने वाले छात्रों को दिया जाता है। इन छात्रों के लिए न्यूनतम अंकों की आवश्यकता 60त (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 55त) होती है। संस्थान की अलग अलग ब्रांच में 3,000 से अधिक सीटों उपलब्ध है। छह दशक से अधिक समय से रिसर्च एक्सीलेंस की विरासत के साथ और भारत में प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों (नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग प्रेमवर्क) में 20वें स्थान पर रैंकिंग प्राप्त करने के साथ, टीआईईटी इंजीनियरिंग के उन छात्रों के लिए एक प्रमुख और पसंदीदा जगह है जो एकेडमिक एक्सीलेंस की तलाश में है। टीआईईटी

सुदूर वनाचल सहित मैदानी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करें : कलेक्टर

कवर्धा(विश्व परिवार)
कलेक्टर महोबे ने आज
कलेक्टोरेट सभाकक्ष में
अधिकारियों की बैठक लेकर जन-
सामान्य से संबंधित विभिन्न
समस्याओं, मांग और शिकायतों के
कंप्लायांस की समीक्षा की
कलेक्टर महोबे ने कहा कि विभिन्न
विभागों को आम नागरिकों के
समस्या और शिकायते प्राप्त होती
है, वे सभी विभाग निर्धारित समय
में प्रकरणों का निराकरण करने
सुनिश्चित करें। इसके साथ ही
राजस्व के लंबित प्रकरणों का
समय सीमा में निराकरण करने के
निर्देश दिए। उन्होंने जिले सहित
स्थानीय स्तर के सभी कार्यालयों
निर्धारित कार्यालयीन समय में
संचालित करने और सभी
नागरिकों के समस्याओं का
समाधान करने के निर्देश दिए
कलेक्टर ने ग्रीष्मऋतु मौसम के
ध्यान में खबते हुए जिले में लू से



बचाव और आवश्यक तैयारी
जिए अधिकारियों को निर्देश
है। बैठक में अपर कलेज
अविनाश भोई, संयुक्त कलेज
डॉ. मोनिका कौड़ौ, आल
श्रीवास्तव, कवर्धा एसडी

के अनुपम टोप्पो, पंडिरिया
ए ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर
र रायस्त, आरबी देवांगना
एर अजग़ले, आकांक्षा नायर
क जिला अधिकारी उपरिया
म कलेक्टर महोबे ने कहा नि-

गर्मी के कारण अनेक संदीप गीता लेखा सहित थे। अधिक स्तर कम हुआ है, का चिन्हांकन करकी व्यवस्था सुनिनिर्देश दिए। उन्होंने भी गांव में पेयजल

विभाग के उपकी ओला एवं प्रभावित फसल राशि 3 करोड़ राशि बीमा कंपनी खाते में भुगतान शेष राशि भी

हेहे। सभी को करना हमारी जिले के सुदूर अधिक ध्यान देने सीईओ जनपद, एचई विभाग के रूप से गांव में व्यवस्था सुनिश्चित जल से संबंधित की समस्या आने करने के निर्देश फसल नुकसान नों के आरबीसी फसल बीमा के वाली राशि के नारी ली। कृषि चालक ने बताया मौसम बारिश से की बीमा की लाख रुपए की द्वारा किसानों के केया जा चुका है। द ही भुगतान कर दिया जाएगा। कलेक्टर महोबे ने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन विशेष अभियान चलाकर वृहद रूप से पौधरोपण किया जाना है। उन्होंने बन विभाग के अधिकारी को इसके लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के ग्रीष्म कालीन अवकाश की कार्य योजना की जानकारी लेते हुए कहा कि विद्यार्थियों के उचित मार्गदर्शन के लिए कवर्धा के लाइब्रेरी में काउंसलिंग सेंटर प्रारंभ किया जाए। जहां विद्यार्थियों को बेहतर भविष्य के लिए जानकारी मिल सके इसके साथ ही मोटिवेट होकर अपने आगे की पढ़ाई जारी रखें। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी की व्यवस्था भी बेहतर रखें और विद्यार्थियों को इसके लिए प्रेरित करें। ताकि ग्रीष्म कालीन समय में भी लाइब्रेरी का उपयोग कर सके।

परिवार)।	के विरुद्ध धारा 354, 354(क),354(घ), 456, 506,509, 341 भादवि. 8,10,12 पाक्सों एकत्र कायम कर विवेचना में लिया गया प्रकरण नाबालिग बालिका एवं महिला संबंधित होने से उक्त घटना क्रम की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई जिस पर प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा, अनुबिभागीय पुलिस अधिकारी डॉंगरगांव दिलीप सिसोदिया के निर्देशन में थाना प्रभारी घुमका निरीक्षक विनय कुमार पम्मार के नेतृत्व में तत्काल घुमका पुलिस के द्वारा आरोपी को ग्राम गिधवा से सोमवार को ही गिरफ्तार कर न्यायालय राजनांदगांव में पेश किया गया।
----------	--

शारदा विहार के मकान में आईपीएल मैच सट्टा नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार

कोरबा (विश्व परिवार)। सक्ति पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट में अॅनलाइन सदृश खिलाने वाले गिरोह के एक बुकी और सटोरियों को गिरफ्तार किया है। सक्ति निवासी बुकी कोरबा वेशारदा विहार के एक मकान से सेटअप चलाते हुए पकड़ा गय जिसे उसने किराए पर लेकर रख था। सक्ति थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक शर्मा ने बताया कि सक्ति जुआ और सदृश के खिलालगातार कार्रवाई की जा रही है। जिसके चलते अब सदृश कारोबार शहर से बाहर जाकर दूसरे जिले से सदृश के अवैध कारोबार क्षेत्र संचालन कर रहे हैं। सक्ति सटोरियों के सक्रिय होने के



मारी वाहन की टक्कर से कन्वेयर बेल्ट पोल क्षतिग्रस्त, कोयला आपूर्ति बाधित

ई-संजीवनी कंसल्टेन्सी बना मरीजों का हमदर्द

**कपल एक पाइया काल से मराजा का निल
रही है उचित चिकित्सकीय परामर्श**

दंतेवाड़ा(विश्व परिवार)। जिला मुख्यालय के जिला अस्पताल में विगत दो महीनों से प्रारंभ हुई टेलीमेडिसिन की नवीन पहल। जिसे ‘इं-संजीवनी साथी’ कहा जा सकता है। वास्तव में दूर दराज के मरीजों के लिए एक हमदर्द साबित हो रहा है। केवल एक वीडियो कॉल के माध्यम से चिकित्सकों द्वारा मरीजों से सीधे रूबरू होकर उनके शारीरिक व्याधियों के लक्षणों को सुना जाता है और बीमारियों का सूत्र पकड़ते हुए उचित औषधियों के सेवन का परामर्श, परहंज अथवा सीधे अस्पताल आने की सलाह दी जाती है। इस चिकित्सकीय वीडियो कॉम्प्रेसिंग का सबसे बड़ा लाभ उन मरीजों एवं उनके परिजनों को हो रहा हैं जो दूर दराज के क्षत्रियों में निवास

करत है आप तुम सकते। टेलीमेडिया के चिकित्सक प्र हेतु उपलब्ध रह ग्रामीण प्रथमिक से विडियो कॉल सीधे चिकित्सकों को रोगों की गम साथ और उन्हें संविकल्प मिल जाए से ग्रामीण क्षेत्रों आने की जस्तर उपचार प्रारंभ क अस्पताल आने बचत, जैसी अस्पताल में भी सामना नहीं करता

जिला अस्पताल नहा पहुचन के जरिये जिला अस्पताल दिन दो घंटे के लिए मरीजों हैं जहां उन्हें 40 से अधिक वां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों मिलती है और वे लोगों को परामर्श देते हैं। और मरीजों रता का पता चलने के साथ-य पर उचित इलाज कराने का है। इस सुविधा के प्रारंभ होने मरीजों को सीधे अस्पताल में पड़ती है और वे समय रहते सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें ने के खर्च, दूरी, समय की वधाएं होने के साथ-साथ से हो रही असुविधा का भी पड़ रहा है। इस संबंध में ग्रामाणा द्वारा अपन निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ), ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (आरएचओ) से सम्पर्क किया जाता है जहां जिला अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराये गये लिंक के माध्यम से जिला अस्पताल सम्पर्क साधा जाता है और उपलब्ध चिकित्सक मरीजों से मश्वरा करते हैं। तत्पश्चात चिकित्सकों के परामर्श अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ एएनएम एवं सीएचओ द्वारा मरीजों को निशुल्क दबाई दी जाती है। इस संबंध में अस्पताल में उपस्थित टेली कंसल्टेंसी सुनी पूजा डे एवं आरएमए शत्रुघ्न सोनी ने बताया कि जिला प्रशासन की इस पहल से विडियो कॉल के माध्यम से कई मरीजों की बीमारियों की स्थिति का पता समय से पूर्व पता चलने के साथ-साथ उपचार कराने का पर्याप्त समय मिल रहा है।

